देश लगातार बिक रहा है, आपको नहीं दिख रहा है, ये आपकी गलती है.

साइबर नजर

कुछ प्राइवेट कंपनियां देश को अपने हिसाब से चला रही हैं और आपको लगता है, देश सरकार चला रही है.

सरकार अगर अपनी पर आ जाए, तो टैक्स से, वो पूरे देश को शानदार मेडिकल, बिजली, पानी, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, ट्रांसपोर्ट सब कुछ फ्री दे सकती है, जैसे दिल्ली में मिल रहा है, वो भी बिना कोई टैक्स बढाए, लेकिन केंद्र सरकार का उद्देश्य, केवल देश बेचना है, ताकि दुनिया की सबसे अमीर पार्टी बनी रह सके. पार्टी का विकास होना चाहिए, देश कल बिकता हो तो आज बिक जाए, इनकी बला से.

चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन बिकाऊ है..... बोलो खरीदोगे!

चंडीगढ़ में प्राइम लोकेशन पर जमीन के क्या रेट चल रहे होंगे ?.....बस ऐसे ही जानकारी के लिए पूछ रहा हूँ!.....वैसे सुना है कि भारत में अन्य राज्य की राजधानियों की तुलना में, इस संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ में जमीनो की कीमतें शुरू से ही बहुत अधिक रही है.

माना जाता है आज भी मुंबई बेंगलरू के बाद सबसे महंगी जमीन चंडीगढ़ में ही है. दरअसल केंद्र सरकार की मंशा 'चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास' की है ओर PPP मॉडल के तहत इस स्टेशन की जल्द ही बोली लगने वाली है ओर अडानी समूह और जीएमआर सहित कम से कम सात कंपनियां इस चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन की व्यावसायिक पुनर्विकास परियोजना हासिल करने की दौड़ में हैं. हालांकि यह पहला स्टेशन नही है जिसे PPP मॉडल के तहत मोदी सरकार प्राइवेट ऑपरेटर को सौपने जा रही है.

इस से पहले भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन को जुलाई 2016 में बंसल पाथवे को सौप दिया गया था. यह पहला निजी रेलवे स्टेशन है जहाँ रेलवे केवल गाड़ियों का संचालन करेगी तथा रेलवे स्टेशन का संचालन प्राइवेट कंपनी बंसल ग्रुप करेगा. इस समझौते के बाद हबीबगंज रेलवे स्टेशन पर गाड़ियों की पार्किंग से लेकर खान-पान तक बंसल ग्रुप के अधीन होगा तथा इससे होने वाली आय भी इसी कंपनी को मिलेगी.

लेकिन चंडीगढ़ ओर हबीबगंज के PPP कांट्रेक्ट के बीच मे जो मूलभूत अंतर है, वह यह है कि हबीबगंज रेलवे स्टेशन की लीज 45 साल की अवधि के लिए सौपी गयी थी लेकिन अब चंडीगढ़ आनंद विहार, सिकंदराबाद, पुणे और बेंगलूरु सिटी के रेलवे स्टेशन को 99 साल की लीज पर प्राइवेट कम्पनियों को सौपा जा रहा है! ऐसे कुल मिलाकर 68 रेलवे स्टेशन ओर है!

जब पिछली बार यह रेलवे स्टेशन को PPP मॉडल के तहत विकसित करने का जब प्रस्ताव लाया गया था तब बड़ी कंपनियों ने रूचि नही ली थी. उनका कहना था कि इन रेलवे स्टेशनों में निवेश तभी फलदायी हो सकता है जब उन पर रिहायशी इमारतें बनाने की छूट दी जाए. इसके लिए 99 वर्ष की लीज जरूरी है. 2018 के मध्य में मोदी जी की कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी ओर तभी रेलवे ने स्टेशन पुनर्विकास योजना के आकार को घटाकर 400 स्टेशन पर सीमित किया और इनमें से 68 स्टेशनों का पुनर्विकास प्राथमिकता के आधार पर प्रारंभ करने का निर्णय लिया.

इस योजना के लिए 'इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कारपोरेशन' को नोडल एजेंसी बनाया गया ओर उसे रणनीतिक और व्यावसायिक योजना तैयार करने की जिम्मेदारी सौपी गयी...तथा मंत्रालय द्वारा उक्त योजनाओं की मंजूरी के बाद, आइआरएसडीसी तथा अन्य एजेंसियां मिलकर स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए निजी कंपनियों को फ्रीहोल्ड जमीन का हस्तांतरण करेंगी.

जी हाँ, फ्री होल्ड जमींने! वो शहर के सबसे प्राइम लोकेशन यानी रेलवे स्टेशन से बिल्कुल लगी हुई.....

चंडीगढ़ की ही बात करे तो चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन की बोली को जीतने वाली कंपनी को कमर्शियल यूज के लिए करीब 25 लाख स्केयर फुट जगह उपलब्ध होगी, जिनमें 30 फीसदी आवासीय उद्देश्य के लिए होगी.

सूत्र कह रहे हैं कि 'डेवलपमेंट मिश्रित उपयोग वाला होगा, जिससे कंपनियों को फायदा होगा. इसमें स्टेशन परिसर में आवासीय अपार्टमेंट बनाए जाएंगे.

इसके साथ ही परियोजना को अग्रणी बैंकों से बुनियादी ढांचा का दर्जा दिया जाएगा.....यानी अडानी या त्रस्क्रजैसे प्राइवेट कंपनियों को बुनियादी ढांचे विकसित करने के नाम पर सस्ता कर्ज ओर लगभग मुफ्त के भाव 99 साल की लीज पर प्राइम लोकेशन की जमीन और बात करना 'मैं देश नही बिकने दूँगा' की ?

आप ध्यान दीजिए कि प्राइवेटाईजाइशेन के लिए जनता के दिमाग मे यह छवि गढ़ी जाती हैं कि रेलवे स्टेशन पर बुनियादी सुविधाएं भी मौजूद नही है, न ही कोई साफ सफाई है. चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन देश के रेलवे स्टेशन की स्वच्छता रैंकिंग 2006 में जहां छठवें स्थान पर था. वहीं, 2016 में 32वें, 2017 में 48वें, 2018 में 55वें व 2019 में सीधे 130 वे स्थान पर धकेल दिया गया.

इस महीने की शुरूआत में जब रेल क्लीनलिनैस सर्वे टीम ने चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन से सफर करने वाले 333 यात्रियों से बात की. इनमें से 326 लोगों ने स्टेशन की सफाई व्यवस्था को बेहतर बताया लेकिन उसके बावजूद प्रोसैस इवैल्यूवेशन स्कोर में काफी कम अंक चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को दिए गए ....यानी षणयंत्र पूर्वक यह कार्य किया जा रहा है ताकि रेलवे स्टेशन के निजीकरण को सही ठहराया जा सके.....

अगर पूरे देश मे रेलवे के आधिपत्य की जमीनों का सर्वे किया जाए तो यह जमीनें किसी भी छोटे से राज्य से अधिक निकलेगी.....मोदी सरकार इन बेशकीमती जमीनों को कौड़ियों के भाव में 99 साल की लीज अडानी जैसे उद्योगपतियो को सौप देना चाहती है.....यही तो विकास है.....!

'क्रांतिकारी मज़दूर मोर्चा' निगम सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का समर्थन करता है

'हरियाणा कौशल रोज़गार निगम' मज़दूरों के साथ धोखा है

सत्यवीर सिंह

'हमारी सेवाओं को नियमित करो, समान काम-सामान वेतन लागू करो, 4000 रु ज़ोखिम भत्ता दो और हमें कौशल विकास निगम का झुनझुना नहीं चाहिए, कोरोना के दौरान जो सफ़ाई कर्मचारी ड्यूटी करते मारे गए उन्हें 50 लाख रु की मदद दो', इन मांगों को पूरा कराने के लिए, हरियाणा में नगर निगम सफ़ाई कर्मचारी, अग्नि शमन कर्मचारी एवं अन्य नगर निगम कर्मचारी 19 अक्तूबर से हड़ताल पर हैं.नगर निगम दफ़्तरों के प्रवेश द्वारों में ताले लगे पड़े हैं.

हालाँकि, जल आपूर्ति और आपातकाल अग्नि शमन कर्मचारियों को 'हरियाणा नगरपालिका कर्मचारी संघ' ने हड़ताल से बाहर रखा है, जिससे अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा ना आए. क्या कोई सोच सकता है कि नगर निगम के जो कर्मचारी पिछले 30 सालों से नियमित कार्य कर रहे हैं, वे भी अस्थाई ही हैं. मतलब, सेवानिवृत्त होने के बाद उन्हें नियमित कर्मचारियों को मिलने वाली सुविधाएँ, जैसे पेंशन आदि नहीं मिलने वालीं. प्रदेश के विभिन्न नगर निगमों में कुल 25,000 सफ़ाई कर्मचारी हैं, जिनमें मात्र 10,000 कर्मचारी ही नियमित कर्मचारियों की श्रेणी में आते हैं. 15,000 हमेशा अस्थाई ही रहेंगे!!

कर्मचारियों को स्थाई करने की बजाए, हरियाणा सरकार उन्हें 'हरियाणा कौशल रोज़गार निगम' में लाना चाहती है. सफ़ाई कर्मचारी यूनियन इसका विरोध कर रही है और वह बिलकुल सही कर रही है.

'हरियाणा कौशल रोज़गार निगम' की 'सक्षम' योजना 2016 में शुरू की गई थी. इसका घोषित उद्देश्य है, हरियाणा के युवकों को 'कुशल' बनाना, मासिक बेरोज़गारी भत्ता देना साथ ही योग्य स्नातकोत्तर युवकों को, हरियाणा के विभिन्न सरकारी विभागों, निगमों, बोर्ड, सहकारी सोसाइटी तथा निजी उपक्रमों में, 'मानदेय (honorarium)' पर नोकरी देना. हरियाणा में डबल इंजन की सरकार है जो तेज़ी से विकास की आवश्यक शर्त है, ये ज्ञान साहिब-ए-मसनद हर सभा में चीख-चीखकर देते फिरते हैं. भाजपा सरकारों का नामकरण के बारे में जवाब नहीं!! बानगी देखिए; 'कौशल निगम द्वारा युवाओं को 'सक्षम' नोकरी दी जाएगी. कुछ युवा 'द्रोण' मतलब 'पथ प्रदर्शक (mentor) बनेंगे'!! 'द्रोणाचार्य' नहीं लिखा, कहीं एकलव्य का अंगूठा मांगने के अपराध के लिए, लोग दाना-पानी लेकर ही ना चढ़ जाएँ!! अगर जुमलों और लफ्फाज़ी से लोगों के पेट भर जाया करते, संस्कृत वाले नाम रखने से बे-रोज़गारी मिट जाया करती, तो भारत सचमुच विश्वगुरु होता. विश्व भूख इंडेक्स में 107 वें नंबर पर अफगानिस्तान और सोमालिया-सूडान के साथ ना घिसट रहा होता. 'कौशल निगम' की वेब साईट खोलते ही, एक घड़ी तेज़ी से घूमकर इन आंकड़ों पर रुक जाती है; भर्ती- 1,14,146; प्रशिक्षण प्राप्त 1,01,469; मूल्यांकन- 57,255; प्रमाणपत्र जारी- 47,801; नियुक्ति 10,193. मतलब, 2016 से आज तक, 6 साल में कुल 10,193 युवाओं को, वह भी पक्की नोकरी नहीं, 'मानदेय' पर नोकरी दी गई!! ये है 'कौशल निगम' की लिक्षण कुशलता. पिछले 6 सालों में इस योजना के क़सीदे पढ़ने में मंत्रियों-संत्रियों के काफिलों का, विज्ञापनों का और निगम के निगमायुक्त आदि पर कितना खर्च हुआ; ये ब्यौरा देने वाली घडी भी वेब साईट के पहले पेज पर ही दे दी गई होती, तो लोग जान पाते कौन सी घड़ी ज्यादा तेज़ दौड़ रही है!! छ-साल में दस हज़ार युवाओं को मानदेय पर नियुक्ति मिली; ये बात उस राज्य की है जहाँ सरकार का नारा, 'नंबर 1 हरियाणा', बेरोज़गारी में पूरा हो चुका है. प्रदेश बेरोज़गारी में देश में पहले नंबर पर है. सितम्बर में प्रकाशित सेंटर फॉर मोनिटरिंग इंडियन इकोनोमी (CMIE) आंकड़ों के अनुसार, अगस्त आखिर में हरियाणा में बे-रोज़गारी दर 37.3 प्रतिशत रही जो देश के औसत 8.3 प्रतिशत से 4 गुना ज्यादा है.

'हरियाणा कौशल रोज़गार निगम' का असल मक़सद, दरअसल, बे-रोज़गारों को कौशल विकास के नाम पर उलझाए रखना है. युवाओं में रोज़गार मिलने की झूटी लालसा बुझनी नहीं चाहिए, यही इस उपक्रम का उद्देश्य है. वर्ना अगर हरियाणा सरकार को, युवाओं को नोकरी देनी होती, तो हरियाणा में स्कूल शिक्षकों के 38,000 से अधिक पद रिक्त ना पड़े होते, वहां भर्ती करने की बजाए स्कूलों को बंद या एक-दूसरे में मिलाने के बाद शिक्षकों के 20,000 पद समाप्त करने की क़वायद ना चल रही होती.

छोटे से राज्य में लाखों सरकारी पद रिक्त ना पड़े होते. ना सिर्फ रोज़गार नहीं देना है बल्कि अगर कहीं देना भी पड़े तो उन्हें महज़ 'मानदेय' मिले, वेतन नहीं. वेतन कम भी हो, तो भी वह हक़ का पैसा होता है. 'मानदेय' का तो अर्थ ही होता है, जैसे किसी की कृपा से मिल रहा है. जिसे बढ़ाने को कहना भी अज़ीब लगता है.

साथ ही, मानदेय के साथ दूसरी सेवा सुविधाएँ नहीं होतीं. ना पेंसन, ना ग्रेचुटी, ना ईलाज सुविधा, ना छुट्टियाँ. सफ़ाई कर्मचारी समझदार हैं, इसी लिए, इस तरह मूर्ख बनने से इंकार कर चुके हैं. उनका आन्दोलन एकदम जायज़ है. कर्मचारी को सालों साल अस्थाई रखना, नियमित ना करना अन्यायपूर्ण है. ये उनके शोषण को अधिकतम करने की साजिश है. हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल द्वारा, सफाई कर्मचारियों की मांग पर चुप्पी साध लेना या उन्हें हरियाणा कौशल रोज़गार निगम की योजना के तहत अस्थाई से भी ज्यादा अस्थाई बना देने का ऑफर देना जिसे कर्मचारी पहले ही ठुकरा चुके हैं, और बार-बार 'लोगों को हो रही असुविधा' के तहत हड़ताल वापस लेने की गुहार लगाते जाना एक चालाकी पूर्ण चाल है. इससे जन-मानस में कर्मचारियों के प्रति दुर्भावना पैदा होती है. जबकि हकीक़त ये है कि ये बिलकुल न्यायोचित मांग सफ़ाई कर्मचारी बार-बार उठाते रहे हैं. सरकार द्वारा उनकी मांग को अनदेखा करने पर ही उन्हें हड़ताल पर जाना पड़ा. समान काम का समान वेतन होना चाहिए, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट दे चुकी है जिसे सरकार द्वारा ना लागू करना, सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है. इसलिए, हड़ताल से जन-मानस को हो रही असुविधा के लिए सफ़ाई कर्मचारी नहीं, बल्कि हरियाणा की संवेदनहीन सरकार ज़िम्मेदार है.

केंद्र सरकार हो या कोई भी राज्य सरकार, उनकी रोज़गार नीति बिलकुल सामान है. 'कोई भी रिक्त पद ना भरो, रिक्त पदों को समाप्त करने के तरीक़े खोजो, अगर कुछ नियुक्तियां करनी भी पड़ें तो अस्थाई, तात्कालिक, ठेके पर, अतिथि की तरह करो, जिससे रोज़गार दिए जा रहे हैं, ये आभास तो होता रहे लेकिन असलियत में युवा, ना बा-रोज़गार रहे और ना बे-रोज़गार. हाँ, अगर 50 करोड़ बे-रोज़गारों में, 50 हज़ार को भी काम पर लिया जा रहा हो, तो भी उनके नियुक्ति पत्र ढोल-ढमाके के साथ, समारोहपूर्वक दो, उसके विज्ञापन महीनों तक चलाओ.' लोगों ने अब इस छल-कपट में फंसने से इंकार कर दिया है. सफाई कर्मचारी संघर्षों के रास्ते पर चलते आए हैं. उन्होंने कई लड़ाइयाँ लड़ी और जीती हैं, इसे भी जीतेंगे. 'क्रन्तिकारी मज़दूर मोर्चा, फरीदाबाद' हरियाणा के नगर निगम सफाई कर्मचारियों के संघर्ष में उनके साथ है. हिसार जिले में पुलिस द्वारा, ठीक दिवाली के दिन 300 के क़रीब सफाई कर्मचारियों को गिरफ्तार करना, जिनमें अधिकतर महिलाऐं हैं; एक दमनकारी, अमानवीय कार्यवाही है जिसका तीखा प्रतिकार प्रदेश के सभी मज़दूरों ने मिलकर करना चाहिए, ये आह्वान करता है. समय आ गया है, जब संघर्ष कर रहे विभिन्न तबक़ों को एकजुटता क़ायम कर, एक संयुक्त मंच बनाना चाहिए.

मंहगाई और बे-रोज़गारी के मुद्दों पर, शोषित-पीड़ित तबक़े की तहरीक को खंड-खंड कर कमजोर करने के सरकारी मंसूबों को नाकाम करते हुए राष्ट्रव्यापी, जन-आन्दोलन की एक प्रचंड लहर पैदा की जाए, जिससे इस मरणासन्न शोषणकारी, दमनकारी, आदमखोर पूंजीवादी-साम्राज्यवादी व्यवस्था से हमेशा- हमेशा के लिए मुक्ति मिले.